"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 09, Issue: 01, Jan. – Feb. 2022 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 6.02

भारतीय शासन एवं राजनीति पर कोरोना महामारी का प्रभावः एक विश्लेषण

अशोक कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय महाविद्यालय,
छत्तरगढ (बीकानेर) राजस्थान

सारांश

वैश्वीकरण में केवल वस्तुओं और सेवाओं का ही तीव्र आवागमन नही होता है, अपितु महामारियां भी पलक झपकते ही वैश्विक हो जाती हैं। दुनिया के सभी देश कोरोना महामारी के अलग–अलग स्तर (Stage) का सामना कर रहे हैं। भारत में भी यह माहामारी विकराल होती जा रही है। स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव धीरे धीरे महसूस किया जा रहा है। जहाँ तक घरेलू राजनीति पर कोविड– 19 के असर की बात है, राजनीतिक विश्लेषक लगातार नागरिक समाज का ध्यान बदलावों की ओर खींच रहे हैं। घरेलू राजनीति पर कोविड–19 के विश्लेषण के लिए प्राथमिक तथ्य संकलन में अवलोकन विधि और द्वितीयक तथ्य संकलन में पुस्तकें, अखबार, पत्र–पत्रिकाएं और इंटरनेट का उपयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य नीति निर्माताओं और नागरिकों को बदलती राजनीतिक स्थिति से अवगत कराना है, ताकि बदलावों को समझ सकें और सहज हो सकें। अध्ययन में सामने आया है कि, भारत में कोविड–19 का असर संघीय ढांचे , राज्य के स्वरूप, लोकतंत्र की प्रकृति, चुनावी मुद्दे, मतदान व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में देखा जा रहा है।

बीज शब्द–सहकारी संघ, निजीकरण, पुलिस राज्य, सहभागी लोकतंत्र, वामपंथ, मनरेगा।

भारतीय शासन एवं राजनीति पर कोरोना महामारी का प्रभावः एक विश्लेषण

बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, किंतु कुछ घटनाएं इतनी बड़ी घटती हैं और इतने सारे बदलावों को जन्म दे जाती हैं कि, वे इतिहास में युगान्तकारी घटना के रूप में दर्ज हो जाती हैं। इतिहास में झांक कर देखते हैं तो हमें औद्योगिकरण, प्रथम विश्वयुद्ध,द्वितीय विश्वयुद्ध और वैश्वीकरण इसी तरह की युगान्तकारी घटना के रूप में दिखते हैं,जिन्होंने कमोबेश जीवन के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव को जन्म दिया। विश्लेषक कोविड़–19 को एक ऐसी ही विभाजक घटना के रूप में देख रहे हैं, जिसके बाद की दुनिया पहले की दुनिया से

बहुत जुदा होगी। अलग–अलग क्षेत्रों में विश्लेषक कोविड़–19 के प्रभावों का अध्ययन कर रहें हैं और उन प्रभावों का आंकलन लगा रहे हैं जो भविष्य में प्रकट होंगे। राजनीति विज्ञान का अध्येयता होने के नाते हमने भारत की घरेलू राजनीति पर कोरोना महामारी के असर का अवलोकन और विश्लेषण किया है। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हमने विश्लेषण को बिन्दुवार प्रस्तुत किया है :–

- संघीय व्यवस्था मजबूत बनकर उभरी है–

संघीय व्यवस्था की आलोचना में आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि, यह संकटकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। एकात्मक व्यवस्था को संकटकाल के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता रहा है।[1] किंतु कोविड–19 के विरूद्ध केन्द्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय से यह विश्वास कायम हुआ है कि, संघीय व्यवस्था मुश्किल समय में भी कारगर है। भारतीय संविधान में संघवाद के जिस सहकारी रूप की कल्पना की है, उसे कोरोना महामारी के विरूद्ध संघर्ष में हकीकत में बदलते देखा है। केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों ने अपने राजनीतिक मतभेदों को किनारे करते हुए, सूचनाओं और चिकित्सा परामर्शों का तेजी से आदान–प्रदान किया। केन्द्र ने प्रान्तों की ओर से आने वाले सुझावों को पूरी गंभीरता से लिया और लागू भी किया। मसलन–राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस टेस्टिंग किट की खामियों से केन्द्र सरकार को अवगत कराया, तो केन्द्र ने तुरन्त प्रभाव से उन टेस्टिंग किटों के प्रयोग पर देशभर में रोक लगा दी। प्रधानमंत्री ने कई दफा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग से बैठकें आयोजित की, जो काफी गंभीर और उदेश्यपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री ने कोरोना के विरूद्ध बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्रियों की खुलकर प्रशंसा की। उदाहरणार्थ–कोरोना के विरूद्ध भीलवाड़ा मॉड़ल [2] के लिए प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और गौरखपुर मॉडल के लिए उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की। सहयोग केवल केन्द्र–राज्य में ही नहीं दिखाअपितु राज्यों में भी परस्पर दिखा है। केरल ने अपने स्वास्थ्य मॉडल की बारीकियों से तेलंगाना,कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को अवगत कराया है। इसी तरह का सहयोग लॉक डाउन के निर्देशों की पालना, जरूरी सेवाओं की आपूर्ति और छात्रों व मजदूरों को घर पहुँचाने में केन्द्र–राज्य और राज्य–राज्य में दिखा। यद्यपि पं. बंगाल के मामले में केन्द्र और राज्य में थोड़ा सघर्ष दिखा, किन्तु यह अल्पकालिक और आपवादिक था। कोविड–19 के विरूद्ध संघर्ष में बड़ा परिदृश्य केन्द्र और राज्यों में परस्पर सहयोग का उभरा है।

- लोक कल्याणकारी राज्य का महत्व बढ़ा है –

भारत की मूल प्रकृति तो कल्याणकारी राज्य की है, और वह आज भी है, किंतु वर्ष – 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के निजीकरण के फैसले ने भारत में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को छोटा कर दिया है। राज्य के बहुत से कार्य निजी हाथों में चले गए हैं। [3] भारत में निजीकरण की प्रक्रिया पिछले तीन दशक से आगे ही बढ़ रही थी। हर सरकार अर्थव्यवस्था के किसी ने किसी क्षेत्र में निजी निवेश को मंजूरी दे रही थी। किंतु कोविड–19 ने न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया को ठहरकर यह सोचने को मज़बूर किया है कि, क्या निजीकरण ही विकास का सर्वोतम मार्ग है! क्योंकि कोविड – 19 के विरूद्ध अभियान ने सीमित राज्य की नाकामी को उजागर किया है। यह नाकामी भारत में ही नहीं अपितु दुनिया भर में दृष्टिगत हुई है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ यूरोपीय संघ इस महामारी के विरूद्ध असहाय नजर आया। भारत आज कोविड –19 के विरूद्ध संघर्ष कर पाया तो उसके पीछे राज्य के बचे हुए लोक कल्याणकारी स्वरूप की भूमिका रही है। सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता से ही देश मुश्किल समय का सामना कर पाया है। ग्राम स्तर से राजधानी तक सरकारी चिकित्सालय मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लॉक डाउन में पुलिस चौबीस घण्टे संघर्षरत् दिखी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् मिलने वाले राशन की घर–घर तक पहुँच सुनिश्चित की गई। ई–मित्र के माध्यम से पेंशन पहुँचाई गई। विदेशों में फंसे भारतीयों या अन्तरराज्य सीमा में फँसे मजदूरों और छात्रों को घर पहुँचने में सरकारी तंत्र ही कार्यरत् दिखा। क्वारेन्टाइन केन्द्रों पर सरकारी विभागों के कर्मचारी ड्यूटी देते नजर आए। किंतु भारत में कोविड–19 महामारी सें निपटने में निजी चिकित्सालयों की भूमिका सीमित और महंगी दिखी। भारत की यह खुशकिश्मत है कि इसने अपने सार्वजनिक क्षेत्र को बचा के रखा है। कल्पना कीजिए, यदि भारत में एक भी सकारी अस्पताल न होता तो कैसे हम इस महामारी का सामना कर पाते ? कोविड–19 महामारी ने फिर नीति निर्माताओं को आगाह किया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को तो सरकार कम से कम निजी हाथों के भरोसे नहीं छोड़े। गौरतलब हैं कि जब देश संकट में होता है तब उसे सेवा और राष्ट्रप्रेम की सर्वाधिक जरूरत होती है क्योंकि इन्हीं मूल्यों के सहारे ही कोई देश आपातकाल से बाहर निकालता है। सेवा और राष्ट्र प्रेम का भाव कल्याणकारी राज्य के साथ जुड़ता है। निजी क्षेत्र तो अधिकाधिक लाभ और आर्थिक हित पर खड़ा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दौर में सेवा और देश प्रेम का भाव कहीं पीछे छूट जा रहा है।

- नेतृत्व की कड़ी परीक्षा

देश को अच्छे नेतृत्व की जरूरत तो हर समय ही रहती है, किंतु संकट के समय नेतृत्व का महत्त्वऔर भी बढ़ जाता है। नेतृत्व कितना दमदार है, इसका परीक्षण भी विषम काल में ही होता है। जो नेता अपनी सूझ–बूझ और कुशल नेतृत्व से देश को संकट से निकाल ले जाता है, वह नायक की तरह देखा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि प्रधानमंत्री की देश में गहरी लोकप्रियता है। अभी तक प्रधानमंत्री कोविड–19 के विरूद्ध आपदा प्रबंधन में कुशल नेता के तौर पर पेश भी आए हैं। किंतु अभी संकट का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। कोविड–19 से उपजी आगामी चुनौतियों से प्रधानमंत्री कैसे निपट पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। एक कुशल नेता का गुण होता है कि वह संकट काल में नागरिकों का मनोबल कमजोर न पड़ने दें। प्रधानमंत्री समय समय पर विभिन्न संचार माध्यमों से जनता से जुड़े रहें हैं और हौसला अफजाई की है। कोविड–19 के विरूद्ध संघर्ष में हमारे सबसे बड़े यौद्धा चिकित्साकर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों के सम्मान और मनोबल को उच्च रखने के लिए जनता ने प्रधानमंत्री के अनुरोध पर तालीऔर थाली बजाने के साथ साथ दीप प्रज्वलन का कार्य किया। समन्वय, नेतृत्व का बहुत बडा गुण है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बराबर समन्वय बनाए रखा है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री ने कई दफा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोविड–19 के विरूद्ध बेहतर कार्य किया उनकी प्रशंसा भी की है। महामारी से निपटनें में भीलवाड़ा मॉडल और गोरखपुर मॉडल की प्रधानमंत्री ने सराहना की। यह दौर केवल केन्द्रीय नेतृत्व के परीक्षण का ही नहीं है अपितु राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व पर भी मुहर लगने का वक्त है। कई मुख्यमंत्रियों ने अद्भूत प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व का परिचय भी दिया है। हमारे सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदाहरण है, जिन्होंने पूरी टीम भावना के साथ इस महामारी के विरूद्ध काम किया है। भीलवाड़ा में कोविड – 19 की विस्फोटक स्थिति से निपटने में उनके कंटेनमेंट प्लान की प्रशंसा देशभर में हुई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मजबूत नेतृत्व की छवि को कायम रखने में सफल रहे हैं। जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी के लिए उनका गोरखपुर मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बना है। [4] वहीं केरल के स्वास्थ्य मॉडल की सफलता ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आत्मविश्वास और कद को उँचाई दी है।

- राजनीतिक बहस के केन्द्र में आर्थिक मुद्दे–

विश्लेषकों का आंकलन है कि कोविड – 19 के अप्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभावों से अधिक भयानक हैं। कोविड–19 ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को रौंद ड़ाला है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रारंभिक आंकलन के मुताबिक कोविड–19 की वजह से दुनिया भर में 25 मिलियन नौकरियाँ जाने वाली हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो यह और भी मुश्किल समय है, क्योंकि कोविड –19 के आने से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत बहुत अच्छी नहीं थी। विकास दर पहले ही पाँच प्रतिशत के आसपास चल रही थी और अब तो यह ऋणात्मक (-23) हो गई हैं। इसी तरह कोरोना से पूर्व दिसंबर – 2019 में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही हैं। लॉक डॉउन के कारण केवल अप्रेल माह में छः करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। यों तो आर्थिक मुद्दे राजनीति को कमोबेश हमेशा से ही प्रभावित करते हैं, किंतु जब आर्थिक बदहाली का आलम बहुत गहरा हो, तब आर्थिक मुद्दे अन्य मुद्दों को पीछे छोड़कर राजनीतिक विमर्श के केन्द्र में आ जाते हैं। राजनीतिक दलों को जनता से यह बताना पड़ेगा कि देश को मुश्किल आर्थिक हालात से निकालने के लिए उनके पास क्या रोड़मैप है। आर्थिक मसलों पर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते भी दिख रहे हैं। इसका एक उदाहरण कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी की आर.बी.आई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के साथ आर्थिक मुद्दों पर लम्बी बातचीत के रूप में देखा जा सकता हैं। [5]अन्य राजनीतिक दल भी कोविड–19 के संकट से उपजी नवीन आर्थिक चुनौतियों पर होमवर्क कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई मुख्य चुनावी मुद्दे बनेंगे और मतदान व्यवहार को प्रभावित भी करेंगे। इतिहास में हमारे पास पाँचवें आम चुनाव का उदाहरण है, जब चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारत अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। देश में गरीबी का संकट गहरा रहा था। उसी समय श्रीमती इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्ति सहित कई बड़े आर्थिक कदम उठाए। उसके बाद वर्ष –1971 के लोक सभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ श्रीमती गाँधी मैदान में उतरी और भारी बहुमत से विजयी हुई। [6] आर्थिक संकट का असर आने वाले समय में केन्द्र–राज्य वित्त संबंध पर भी दिखेगा। जी.एस.टी. लागू करते समय केन्द्र ने संक्रमणकाल के लिए काफी वित्तीय बोझ अपने सर ले रखा है। इस समय एक ओर लॉक डाऊन के कारण केन्द्र का राजस्व संग्रहण रसातल में चला गया है, वहीं दूसरी ओर केन्द्र को अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए बीस लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की

घोषणा करनी पड़ी है। इन परिस्थितियों में केन्द्र के लिए राज्यों की वित्तीय मांगों को पूरा करना आसान नहीं होगा।

- वामपंथ की राजनीति के लिए अवसर–

पिछले कुछ वर्षों से भारत में वामपंथ सिमटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व की विचारधारा ने वामपंथ के समक्ष हर जगह मुश्किलें खडी की हैं। आज पूरे भारत में केवल केरल में वामपंथी सरकार हैं। केन्द्र में भी वामपंथ की स्थिति मृतप्रायः है। दरअसल पिछड़े और विकासशील देशों में वामपंथ तब प्रभावशाली होता है, जब राजनीतिक विमर्श में आर्थिक मुद्दे हों। भारत में पिछले दो आम चुनावों में राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व की लहर ने गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे–आर्थिक मुद्दों को पीछे धकेल दिया, परिणामस्वरूप वामपंथ भी हासिए पर चला गया। कोविड – 19 ने देश और दुनिया में वामपंथ को फिर से उभरने का अवसर दिया है। दुनिया भर में उदारवाद और पूंजीवाद, इस महामारी से निपटने में कमजोर साबित हुए हैं। विश्लेषक मानते हैं कि पूंजीवाद और उदारवाद की नीतियों पर चलकर तो कोविड–19 के आर्थिक दुष्प्रभावों से भी नहीं निपटा जा सकता। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो आज़ नरेगा योजना फिर विमर्श में आ गई। लॉक डाऊन में शहर से गाँव लौटे मजदूरों के लिए नरेगा ही अस्तित्व का आधार है। गौरतलब है यूपीए(प्रथम) सरकार में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में नरेगा योजना का प्रस्ताव वामपंथी दलों की ओर से मिला था। वामपंथी दल कोविड – 19 के कारण उपजी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक कारगर रोडमैप जनता के सामने रख पाने और समझा पाने में कामयाब होते हैं तो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल कर सकते हैं। वामपंथ के लिए सुनहरा अवसर इस रूप में भी है कि केरल में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने कोविड–19 के विरूद्ध बहुत शानदार ढंग से काम किया है। कोरोंना संक्रमण और मृत्यु दर पर जिस तरह नियंत्रण पाया है, इसके लिए केरल के स्वास्थ्य मॉडल की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। [7] अलग–अलग राज्यों की सरकारें केरल के स्वास्थ्य विभाग से सलाह मशवरा कर रही हैं। वहीं पिछले दशक से बहुचर्चित गुजरात मॉडल कोरोना के विरूद्ध संघर्ष में लचर साबित हुआ है। राजनीतिक हल्कों से केरल मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की बहस धीरे–धीरे उभर रही है।

- सहभागी लोकतंत्र मजबूत हुआ है–

सहभागी लोकतंत्र सत्ता के साथ जनता की निरंतर और सक्रिय साझेदारी पर बल देता है। सामान्य धारणा है कि, सहभागी लोकतंत्र पश्चिमी देशों में ही व्यवहार में लागू होता है, क्योंकि वहाँ लोग पढ़े–लिखे हैं और अपने हक व कर्त्तव्य के प्रति सजग हैं। पिछड़े और विकासशील देशों

के बारे में यह माना जाता है कि, यहाँ सहभागी लोकतंत्र की बात सिर्फ राजनीतिक नारों में दिखती है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के कारण इन देशों में मतदान के विस्तार को ही लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। किंतु कोविड–19 के विरूद्ध संघर्ष में जनता के अपार सहयोग ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नई इबारत लिखी है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सरकार के लॉक डाऊन के आदेशों की जनता ने अक्षरशः पालना की है। बहुत कम अवसर ऐसे आए, जब पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा हो। जरूरी सामान की दुकानों और बैंकों के सामने लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना करते दिखे। प्रधानमंत्री के आहवान पर लोग चिकित्सकों, पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान और उत्साह वर्धन के लिए ताली और थाली बजाने के साथ दीप प्रज्वलित करते भी नजर आए। मध्यम वर्गीय परिवारों के कितने ही लोग समाज के कमजोर और असहाय तबके के लिए जरूरी वस्तुऐं उपलब्ध कराते दिखे। कर्मचारियों ने सहर्ष अपने वेतन का एक अंश राहत कोष में आर्थिक सहयोग किया। यह पूरा परिदृश्य बताता है कि, भारतीय लोकतंत्र केवल चुनावी लोकतंत्र नहीं है, अपितु इसका विस्तार नागरिकों की शासन के साथ सतत् और सक्रिय सहभागिता तक है।

- चुनाव प्रचार में संचार तकनीकी को प्रोत्साहन–

चुनाव प्रचार में संचार तकनीकी का प्रयोग तो लगातार बढ़ ही रहा है। कमोबेश हर राजनीतिक दल का अपना आईटी प्रकोष्ठ है, जो लगातार सोशल मीडिया के द्वारा अपने दल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करता है। कोविड–19 से उपजी परिस्थितियों ने चुनावी राजनीति को संचार तकनीकी पर अधिक निर्भर बना दिया है। अब चुनावी रैलियों को वर्चुअल रैली का रूप दिया जाने लगा है। हाल ही में जून माह में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में वर्चुअल रैली का आयोजन किया है। इस रैली के लिए अलग–अलग स्थानों पर दर्शकों और श्रोताओं के लिए 72 हजार एलईडी स्क्रीन लगाई गई।

- पंचायती राज का महत्त्व बढ़ा है–

कोविड –19 महामारी से निपटने में ग्राम पंचायतें अभी तक कारगर साबित हुई है। भले ही ग्रामीण क्षेत्र कोरोना वायरस से शहरी क्षेत्र की तुलना में कम प्रभावित हुआ है, किंतु शहरी क्षेत्रों से लौटे कामगारों की चुनौतियों को कम करने में ग्राम पंचायतें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायतों द्वारा गाँवों में प्राथमिक शिक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा सहयोगिनी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पंचायतें ग्राम के मुख्य मार्गों और स्थानों पर सेनेटाइजेशन का कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायतों ने ग्राम स्तर पर

क्वारेंटाइन केन्द्रों का निर्माण किया है, जहाँ प्रवासी मजदूरों को क्वारेंटाइन किया गया। बहुत–सी ग्राम पंचायतों ने बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी के लिए तंत्र विकसित किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा योजना के बेहतर समन्वय से ग्राम पंचायतें बेरोजगार मजदूरों और असहाय लोगों को रसद सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। कुछ ग्राम पंचायतों ने दिहाड़ी मजदूरों के भोजन के लिए सामुदायिक रसोइयों का आरंभ भी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रही हैं। शहरों से गांव में लौटे श्रमिकों के लिए आजीविका का सहारा मनरेगा ही है। कांग्रेस पार्टी ने तो सरकार से मांग भी की है किवह मनरेगा में वर्ष में 100 दिन की बजाय 200 दिन के रोजगार की गारंटी दे। कोविड'19 महामारी के विरूद्ध ग्राम पंचायतों की भूमिका कितनी अहम है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि, प्रधानमंत्री ने हाल में पंचायती राज दिवस पर ई–कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों से बातचीत करते समय गांवों की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गांवो में सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र, दो गज दूरी के महत्त्व को भी रेखांकित किया।[8]

- कानूनी समीक्षा की जरूरत–

कानून निर्माता किसी भी कानून का निर्माण कितनी भी दूरदर्शिता के साथ क्यों न करें, किंतु कोई भी कानून हर परिस्थिति के लिए संपूर्ण नही होता है। यही वजह है कि दुनिया भर के संविधान में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। आज कोरोना महामारी ने हमारी कई कानूनी रिक्तियों को उजागर किया है। संभव है, कोविड़–19 के अंत के बाद इन कानूनी कमियों पर विचार हो और सुधार किया जाए। मसलन–न्यायपालिका की कार्यवाही में तकनीकी प्रयोग बढ़ाने के लिए संविधान में सुधार करना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की तकनीकी को न्यायिक कार्यवाही में आम बनाना होगा। कोविड़–19 के कारण न्यायपालिका की कार्यवाही काफी बाधित हुई है। यही बात आपातकाल के प्रावधानों के बारे में ही जा रही है, अभी तक अनुच्छेद–352 तहत् राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के आधारों में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है, अब 'महामारी जनित' परिस्थिति को भी राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के आधारों में शामिल करने पर विचार किया जाए। वहीं मध्यप्रदेश में कमलनाथ के इस्तीफे के बाद शिवराजसिंह चौहान बिना मंत्रिपरिषद् के ही सरकार चला रहे थे। प्रश्न उठता है, क्या शिवराजसिंह चौहान सरकार संविधान के दायरे में चल रही थी? यदि चल रही थी तो संविधान के अनुच्छेद–164 में उल्लिखित उस प्रावधान का क्या होगा, जिसमें सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद् में कम से कम

12 सदस्यों की बात कही गई है।[9] के प्रभावों का सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, तो हमारा सामना और भी कानूनी विसंगतियों से होगा।

भारत से कोविड–19 का असर समाप्त नही हुआ है। इस महामारी के प्रभाव का परिदृश्य भी बहुत बड़ा है। अतः अलग– दृष्टिकोणों से विश्लेषण का एक लम्बा दौर चलेगा। आने वाले समय में इस महामारी के राजनीति सहित मानव जीवन के अलग–अलग क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ प्रभाव नकारात्मक भी होंगे तो कुछ प्रभाव सकारात्मक होगें। हर देश की कोशिश है कि, वह काविड–19 के दुष्प्रभावों को कम करे और सकारात्मक प्रभावों को अवसर के रूप में ले । मुश्किल समय केवल मुश्किल पैदा करने के लिए ही नही आता है, अपितु हमारी व्यवस्था की क्षमता का परीक्षण करने और हमे नई दिशा देने भी आता है। जैसा कि प्रधानमंत्रीने 12 मई के अपने भाषण में कहा कि कोविड–19 ने हमे आत्मनिर्भर बनने की बहुत बड़ी सीखदी है। यदि हम आत्मनिर्भरता हासिल करने में कामयाब होते हैं, तो 21 वीं सदी भारत की होगी अतः राजनीति को नई चुनौतियो के संदर्भ में स्वयं को भी बदलना होगा और देश को भी बदलना होगा।

संदर्भ–

1. गाबा,ओम प्रकाश, 'राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा' मयूर पेपरबैक्स प्रकाशन, नोएड़ा, तृतीय संस्करण–2016,पृ.संख्या 158
2. Corovirus lockdown:What is Bhilwara Modle? 'India Exress' paper.11th April, 2020

https://indiaexress.com/article/expained/explaind-bhilwara-model-ruthless-containment

-stop-coronavirus-6350395/

3- Sitapati,vinay' Book 'Half-Lion:How P.V.Narasimha Rao Transormed india' Viking publisher, First edition-2016, Page No-156
4- Delivery of essential supplies: Centre may replicate Gorkhpur Modle Times of india 15th april 2020 https://m.timesoindia.com/city/luknow/centre-may-replicate-gorakhpur-modle/amp_articleshow/75150396.cms#aod=1589014631&referrer=htps%3A%2Fwww.google.com&amp_tf=Form%20%251%24s
5. राहुल गाँधी–अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार को दी सलाह बीबीसी हिन्दी 5 मई 2020

https://www.bbc.com/hindi/social-52544502

6. दुबे अभय कुमार , पुस्तक लोकतंत्र के सात अध्याय, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली प्रथम संस्करण2002 पृ संख्या 173
7- कुरैशी,इमरान,बीबीसी हिन्दी संवाददाता की रिपोर्ट कोरोना वायरसः केरल ने लगाई कैसे लगाम 15 अप्रेल 2020 https://www.bbc.com/hindi/india-52290247
8. दो गज दूरी महामारी से लडने में बनायेगी आत्मनिर्भर दैनिक भास्कार दिनांक 25 अप्रेल 2020 प्रथम पृष्ठ
9. कश्यप, सुभाष हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट प्रकाशन संस्करण 2016 पृष्ट संख्या 190